SHRI MADHAVRAO SCINDIA : There are some pilots who have gone over to private air taxi operators though the Indian Airlines job, personally I think, is far more attractive. The pilots of the Indian Airlines are flying between 40 and 80 hours a month whereas the private air taxi pilots are made to fly for over 80 hours a month, within the regulations. But they are made to fly to their full capacity. This can be up to 120 hours a month. So on an hourly basis, if you compare the two, the Indian Airlines pilots are earning as much as 20% more than what is paid by the private air taxi operators. Of course, they are wanting more pay. But there is an incentive package which is being offered : 'fly more and earn more. But somehow they seem to be sticking and wanting to earn more while flying the same number of hours. That is what the management has informed us. So I think that it is attractive from the point of view of salary also as I said, they are earning 20% more per hour flown. At the same time, there is also greater job security. I think it is a far more attractive jib. But this is a free country and if some pilots want to go, exercise their option to go somewhere else, they are free to go. Of course, now we have tightened the bonds for the new pilots who are coming in. We have increased the amount—again I speak from memory—from Rs. 7 lakhs to Rs. 10 lakhs because it does cost money to train a pilot. We are trying to tighten up that end. But for those pilots who joined earlier, of course, that part does not apply. It is only for the new entries that we are taking this action now. So this will be applicable for the new sets of pilots who are coming in.

SHRI KAMAL MORARKA : Sir, the 'Open Sky Scheme' has announced by the predecessor Government did not envisage a parallel commercial airline. By the very nomenclature, the term 'air taxi' implies that the aircraft can be chartered by individual parties like a taxi. What is happening now is that in the name of air taxis, parallel air services have started. They are selling tickets for the Bombay-Delhi route which is totally illegal. As my friend, Mr. Dineshbhai Trivedi, read out an extract from the Air Corporations Act, it was neither envisaged in the Open Sky Policy nor was it the intention of Parliament to start a parallel Indian Airlines. The day we want to do it, we should discuss it properly, debate it fully and then do it. I would request the Minister to tell the House whether the Minister will take steps and not that air taxis are run only as taxis and not as parallel air services, at least till such time the Air Corporations Act is amended.

SHRI MADHAVRAO SCINDIA : Sir, this is open to many interpretations. I have said it is possible within the framework of the Open Sky Policy announced by the hon. Minister on the floor of the House.

Complaints of Faulty Telephone

*102. DR. BAPU KALDATE : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there are common complaints of over billing, faulty phones and corruption against MTNL;

(b) whether it is also a fact that phones remain dead for several days but the 14 days limit is not crossed, if so, whether Government would consider reducing this limit of 14 dyas to 7 days so that the concerned staff works efficiently; and

(c) if so, by when this is likely to be done; and if not, what are the reasons therefore ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI P. V. RANGAYYA NAIDU) :

(a) There are a few complaints of overbilling, faulty telephones and corruption in MTNL.

(b) Efforts are made and in most of the cases the telephones reported faulty are cleared by the following day. Even telephones affected due to interruption on underground cables or cable theft are also generally attended to within a week. A few difficult cases however to take some more time. Department of Telecommunication has however already decided with effect from 15-6-90 to allow prorata rebate in rental if a telephone remains out of order continuously for seven days or more for departmental reasons. If the

telephone remains suspended/interrupted continuously for more than 14 days due to departmental reasons, full month's rental is waived on the Department's own initiative without waiting for any representation/request from the subscriber.

(c) Not applicable in view of (b) above.

डा० बापू कालदाते : सभापति महोदय, मैं तो पहले अपनी शिकायत कर देता हूं कि कितनी उपेक्षा सम्मानीय इस सदन के जो सदस्य हैं उनकी भी होती है। हमने 13 मार्च को चिट्ठी लिखी बम्बई के जो उप महाप्रबन्धक हैं, उनका जवाब नहीं आया। 25 मई को दूसरी चिट्ठी लिखी उसका भी जवाब नहीं आया। एक एकनालेजमेंट रजिस्टर्ड लेटर लिखा, मेरे पास उसकी कापी है, जो रजिस्टर्ड लेटर की प्रति आती है, उस पर दस्तखत नहीं हैं। हमने तीसरी चिट्ठी लिखी कि एक मेम्बर पार्लियामेंट आपको चिट्ठी लिखता है उसका जवाब आप क्यों समय पर नहीं देते हैं, इस बीच आपको चिट्ठी लिखी तो आपका तुरन्त जवाब आया। लेकिन आपके अधिकारीगण जो होते हैं वे क्या हम लोगों को नीचा दिखाना चाहते हैं? हम लोगों की चिट्ठियों का जवाब देने का समय भी उनके पास नहीं है। आप तो कई आप सभायें करते हैं और राज चलाते हैं। लेकिन जो आपके कर्मचारीगण और अधिकारीगण हैं वे समझते हैं कि पार्लियामेंट के मेम्बर की चिट्ठी का जवाब तीन महीने तक भी देने की आवश्यकता नहीं है। यह उपेक्षा निन्दनीय है। इसके लिए दूसरा शब्द कोई नहीं हो सकता है। आपकी तरफ से जवाब मिला। यह अगर हमारी हालत है, यह स्वयं मेरा अनुभव है तो मैं नहीं समझता कि और लोगों की शिकायतों का क्या जवाब आपके अधिकारीगण देते होंगे? आप खुद गये थे 14 नवम्बर को आपने खुफिया तौर पर देखा होगा कि क्या हालत चलती है। मेरे दो सवाल हैं। ओवर बिलिंग की बात हमने कही है। मैं कहता हूं कि अन्डर बिलिंग भी हो सकती है। मैं मानता हूं कि अन्डर बिलिंग भी पोसिबल है। वैसे भी आपने स्टडी किया होगा खुफिया बनकर, तो वैसे ही ओवर बिलिंग भी हो सकता है। इसलिए क्या कोई व्यवस्था आपने कर रखी है जिससे यह हेराफेरी न हो सके? क्या आप ऐसी व्यवस्था कर पाये हैं या नहीं, मुझे मालूम नहीं है। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि मेरे घर पर एक टेलीफोन लगा हुआ है। हमने उसकी शिकायत की, सात दिन हो गये हैं वहां पर एक मशीन रख दी गई है जिसमें कोई जान नहीं है। इसको सात दिन हो चुके है यह क्यों रख दिया गया है? क्या यह बच्चों के खेल के लिए है? इस प्रकार की जो नेग्लिजेन्स है, शिकायतें करते हैं चिट्ठियां लिखते हैं, ओवर बिलिंग होती है, टेलीफोन ठीक नहीं चलते हैं और इस बारे में जो उपेक्षा होती है उसको दूर करने के लिए क्या कोई ठोस उपाय आपने किया है और इसके बारे में कोई कार्यवाही करने के बारे में आपने कोई ठोस उपाय किया है या नहीं, यह मैं जानना चाहता हूं।

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : सभापति जी, पहले मुझे खेद है कि माननीय सदस्य को तीन रिमाइन्डर देने के बाद भी जवाब नहीं मिला। साथ ही मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि ऐसी जरूर कार्यवाही की जाएगी जिससे कि अधिकारीगण माननीय सदस्यों को तुरन्त जवाब दें और आयन्दा ऐसे केसेज कम होंगे ऐसा विश्वास मैं सदन को दिलाता हूं . . . (व्यवधान)।

श्री अजीत जोगी : इस प्रकरण में आप दण्ड देंगे या नहीं यह हम जानना चाहते हैं . . . (व्यवधान)।

श्री राजेश पायलट : सभापति जी यह बात सही है कि हमारा विभाग जनता का

सेवा के लिये है । इस कल्चर को विभाग में लाने की हम पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हमने निर्देश दिये हैं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो हमारी यूनिट्स हैं, वहां हर यूनिट में ओपन सैशन हो, जिसमें आम नागरिक आम सब्सक्राइबर अपनी तकलीफ बता सके । इससे इसमें कुछ सुधार आया है । सोशल आडिट पैनल भी इसीलिए लगाया था कि कुछ बातें जो विभाग द्वारा न पहुंच पायें, विभागीय अधिकारियों द्वारा न पहुंच पायें वह सोशल आडिट पैनल जिसमें रिटायर्ड चीफ जस्टिस भगवती जी, खुशवंत सिंह जी जैसे प्रामिनेंट सिटिजन हैं, उनको रखा है और वे सारे देश में घूमकर असलियत हम तक पहुंचायें जिससे सरकार कुछ ठोस कार्यवाही कर सके । दूसरी बात जो ओवर–बिलिंग की माननीय सदस्य ने उठायी है, यह बात सही है कि कई जगह ऐसी शिकायतें आयी हैं, जहां ओवर–बिलिंग हुई है उसके कारणों का पता लगाने की कोशिश की है और तभी हमने एक फैसला लिया सभापति जी कि अगर टेलीफोन 14 दिन से ज्यादा खराब हो तो उसका रेंटल नहीं लेंगे । इसके पीछे दो कारण हैं एक तो यह कि डिपार्टमेंट में एकाउन्टबिलिटी लिये जिस डिपार्टमेंट का रेवेन्यू कम आयेगा तो मुझे पता लग जायेगा कि वहां टेलीफोन ज्यादा खराब रहे और मैं उन अधिकारियों के खिलाफ विभागीय अधिकारियों के खिलाफ कठोर कदम उठा सकूं और उस सेक्शन को देख सकूं कि उसको किस तरह से और ठीक किया जाय । तीसरा जब रेवेन्यू कम होगा तो विभाग में भी बात चलेगी कि रेवेन्यू में क्यों कमी हुई है । इससे उसमें सुधार होने की उम्मीद होगी । जहां तक बिलिंग की बात है बिलिंग की शिकायत हो तो विभाग ने फैसला लिया है कि पिछले 6 महीनों का एवरेज जो उपभोक्ता का है वह जमा कर दे और ऊपर का जो बिल होगा, जब तक वह क्लियर न हो तब उपभोक्ता का टेलीफोन नहीं कटेगा । सभापति जी, मैं सदन को साफ बताना चाहता हूं कि विभाग की जहां सेवा की ड्यूटी होती है, वहां किसी भी विभाग में कोई न कोई कमी और थोड़ी बहुत इस तरह की बातें जरूर होती हैं । इस ओर हमारे प्रयास जारी हैं । जो भावना माननीय सदस्य की है वह मैं और मेरे साथी जो नायडू जी हैं, उनसे भी इस बात को पूछें कि हम उसी भावना को विभाग में लाने की कोशिश कर रहे हैं । आप विश्वास रखें कि प्रयास जारी है और बहुत जल्दी इसमें सुधार करने की कोशिश की जायेगी ।

श्री चिट्ठलभाई मोती राम पटेल : अपने जनरल मैनेजर को पूछो, चिट्ठी का जवाब देते हैं वे । . . . **(व्यवधान)** खन्ना को पूछो ।

WELCOME TO PARLIAMENTARY DELEGATION FROM THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

MR. CHAIRMAN : Hon'ble Members, I have an announcement to make.

We have with us, seated in the Special Box, Members of a Parliamentary Delegation from the People's Republic of China, currently on a visit to our country, under the distinguished leadership of His Excellency, Mr. Liao Hansheng, Vice-Chairman of the Standing Committee of the National People's Congress of China and Chairman of its Foreign Affairs Committee.

On behalf of the Members of the House and on my own behalf, I take pleasure in extending a very hearty welcome to the Leader and other members of the Delegation and wish our distingushed guests a very enjoyable and fruitful stay in our country. We hope that during their stay here they would be able to see and learn more about our parliamentary system, our country and our people, and their visit to this country will further strengthen the friendly bonds that exist between India and the People's Republic of China.

Through them we convey our greetings and best wishes to the members of the National People's Congress and the friendly people of the People's Republic of China.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS— (Contd.)

डा० बापू कालदाते : अब जो दूसरी बात आपने कही है अगर 14 दिन तक नहीं चलेगा इसमें एक बात जो आपने कही है कि फार सेवन डेज और मोर फार डिपार्टमेंटल रीजन, यह सबसे बड़ी गड़बड़ी की बात है । अगर वह लोग हमको टेलीफोन केबल फाल्ट है यह रोज कहते रहें, हमको पता कैसे चलेगा कि केबल फाल्ट है या डिपार्टमेंटल रीजन है यानी It is human reason that they can delay the things

मैं आपको एक अनुभव बताता हूं । हमारे मित्र के यहां केबल वाली डिफिकल्टी बतायी थी । लेकिन वायरमैन के साथ उन्होंने दोस्ती की और उसको 200 रूपये दिये उनकी केबल तुरंत दुरुस्त हो गया । तो यह है क्या ? क्योंकि हमको पता लग रहा है कि कभी-कभी कर्मचारीगण कहते हैं कि भई हम कुर्सी पर बैठने की तनख्वाह लेते हैं और काम का पैसा लेते हैं, इसमें करप्शन की बात कहां आती है । मैं बैठता हूं उसके लिए मुझे तनख्वाह मिलती है और जो काम करता हूं उसका पैसा लेता हूं । इसमें करप्शन कुछ नहीं है । पैसा दो और तुरंत काम हो जाएगा । इसके बारे में सख्ती की जानी चाहिए । क्योंकि हम को लगता है कि There is also some difficulty. आप हम को इतनी फिगर्ज बता दें कि इस कारण आपने कितने लोगों के पैसे वापिस किये हैं या वेव किये हैं । क्या आप यह आंकड़े मुझे दे सकते हैं कि कितने लोगों ने शिकायत की और 14 दिन के अन्दर उनके टेलीफोन ठीक नहीं हुए और आपने उनका रेंटल माफ कर दिया ? अगर आपके पास ऐसे आंकड़े हैं तो मैं आप से जानना चाहता हूं ।

एक और सख्त शिकायत मैं आपसे करना चाहता हूं । मेरे हाथ में एक फ्रीडम फ़ाइटर का केस है । मंत्री जी ने 10 अगस्त को इस सदन में यह बयान दिया था कि फ्रीडम फाइटर्ज का रेंटल हाफ लगेगा । यह नवम्बर का बिल मेरे हाथ में और इस फ्रीडम फाइटर को मैं कई सालों से जानता हूं । आप इस बिल को देखिये । इसमें जो रेंटल लगा हुआ है वह वही रेंटल है जो हम सब लोग देते है । मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है ? क्या वह फ्रीडम फाइटर उनके दरवाजे पर जा कर बैठे और कहे कि मैं फ्रीडम फ़ाइटर हूं मुझे भीख दीजिये ? अपने आप ऐसा क्यों नहीं होता है ? अगस्त की 10 तारीख का आपका बयान है, Why has this been happening ?

आपने कहा था कि फ्रीडम फाइटर्स के लिए मैं करूंगा लेकिन ऐसा नवम्बर के बिल में नहीं हुआ है ? क्या आपके अधिकारी सो गये हैं । यह तो फ्रीडम फाइटर्ज की बेइज्जती करने के बराबर है । This is very unfair, I should say.

MR. CHAIRMAN : Please. You have made your point.

डा० बापू कालदाते : ऐसा क्यों होता है, यह मेरी समझ में नहीं आता । आप कुछ कोशिश कर रहे हैं । लेकिन आप जरा अपने विभाग के कर्मचारियों का फ्रीडम फाइटर्ज के बारे में बयान देते हैं या आश्वासन देते हैं उसके बारे में भी बता दें और यह कह दें कि उसको वे पूरा करें । खास कर के ऐसे लोगों के लिए जरूर करना चाहिए यह 70 साल के आदमी हैं, क्या उनके पास जाते रहें । मुझे इस बात का बहुत दुख है कि ऐसे लोगों की शिकायतें आपके कर्मचारीगण न सुनते हैं, न देखते हैं और न सोचते हैं । आप उनको कैसे मजबूर करेंगे या मजबूत बनायेंगे कि इस प्रकार की शिकायतों की तरफ वे ध्यान दें और इस दिशा में आप क्या करना चाहते हैं, इतना बता दीजिये ।

श्री राजेश पायलट : सभापति महोदय,.. जहां तक बिलिंग की बात है अब तक सिस्टम

ऐसा था कि बिल डिस्ट्रिक्ट सर्कल से बनते थे । एक प्रिंटिड मोहर लगा कर डिस्पेच कर दिया करते थे । सब्सक्राइबर जब कहता था कि मेरा बिल ज्यादा है या कम है तो शुरुआत होती थी लेकिन अब हम ने इस में सुधार लाया है । एक जिम्मेदार अधिकारी भेजने से पहले उस बिल को देखे । अगर उपभोक्ता का बिल हर महिने दो हजार या ढ़ाई हजार का औसतन आ रहा है और सडनली उसका 50 हजार का बिल आ गया तो रीडिंग देखकर कनफर्म कर के जिम्मेदार अधिकारी उन पर दस्तखत करे । इससे सुधार की शुरुआत हुई है । यह कदम हम लोगों ने उठाये हैं । इसका असर बापू कालदाते जी पूछना चाह रहे हैं । एकदम तो मैं नहीं कह सकता कि इतने दिनों के अन्दर यह हो जाएगा, यह बहुत बड़ा काम है और सारे देश में इसका विस्तार है । कल्चर को चेंज करने में कुछ वक्त लगता है । जहां तक फ्रीडम फाइटर्ज की बात है यह बात सही है और यह सरकार की नीति भी है । इसके विषय में लाल किले में एक समारोह हुआ था उस अवसर पर हमने स्वतंत्रता सेनानियों को देश की तरफ से एक मदद के रूप में कहा था और यह इम्पलीमेंट हुआ है । एक दो केसेज ऐसे हो गये होंगे जहां देखा नहीं होगा कि यह फ्रीडम फाइटर है या सर्टिफिकेट नहीं पहुंचा होगा किसी वजह से गलती हो गई होगी । इस तरह की बात से यह कहना उचित नहीं होगा कि सारे विभाग में फ्रीडम फाइटर्ज को तंग कर रहे है । ऐसी बात नहीं है । ऐसे भी उदाहरण हैं जहां हमारे विभाग के अधिकारी उनके घर पर जा कर दस्तखत कर के टेलीफोन जोड़ कर आए हैं इतने बड़े विभाग में सब तरह के अधिकारी होते हैं । कहीं कुछ गलतियां हो जाती हैं । मैंने पहले भी कहा जो गलतियां हुई, माननीय सदस्यों के पत्रों का जवाब न देना, इसके लिए मैंने खेद जाहिर किया है, मैं इसके निरंतर प्रयास करूंगा कि ऐसी घटनाएं न हों जहां हमारे विभाग की इमेज पर असर पड़े । जहां तक आपने रेंटल के बारे में बात कही है कि 14 दिन के कितने केसेज हुए हैं, इस पालिसी की अभी डेढ़ महीना पहले घोषणा हमने की थी । यह हमारे विभाग की अकाउंटेबिलिटी लाने के लिए थी ताकि यह पता चल सके कि गलती कहां हो रही है । अगर आप नोटिस दे दें तो मैं अब तक के केसेज आपको बता सकता हूं । एक महीने के बाद क्वार्टर की फिगर्ज हमारे पास आ जाएगी । इसी हाऊस में यदि आप दोबारा मौका देंगे तो मैं आपको फिगर्ज दूंगा कि कितने केसेज 14 दिन के हुए हैं जहां हमने रेंटल माफ किया है । यह सदन को बताने के लिए मैं तैयार हूं ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : माननीय सभापति महोदय, मेरा प्रश्न उत्तर के (क) भाग से संबंधित है। अधिक धनराशि के बिल बनाने की शिकायतें आपको मिली हैं, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आपको इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री ब्रहप नाथ काटजू जो एडमांस्टर रोड पर रहते हैं की ओर से इस संबंध में कोई शिकायत मिली है ? और जिनकी शिकायत यह थी करीब 6 महीने पूर्व कि दो महीने में 35,000 रुपये का उनके पास टेलीफोन का बिल आया जबकि घर पर केवल वे और उनकी पत्नी रहती है और उनका कहना यह है कि मेरे टेलीफोन पर बराबर ताला लगा रहता है । मेरे अलावा और कोई टेलीफोन का इस्तेमाल नहीं करता है । अगर यह शिकायत मिली है तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री राजेश पायलट : सभापति जी, मैं इसके लिए टाइम चाहूंगा क्योंकि मैं खास इलाहाबाद की खबर लेकर नहीं आया कि किसकी कम्प्लेंट कहां से आई । माननीय सदस्य को बता दूंगा कि उस पर क्या शिकायत मिली, क्या हमने कदम उठाया है । माननीय सदस्य को लिखकर इसका जवाब दे दूंगा ।

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA : I have an objection. The Minister should have come prepared with the answer. That is why I said that my question relates to part (a) of question. The Minister said that his Department has been receiving complaints of over-billing and my question was, how many complaints were received from Allahabad subscribers, to which he has not replied.

MR. CHAIRMAN : This is something the Minister has to let you know later. He cannot give you the specific details about the number of complaints from Allahabad.

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA : My question was, how many complaints were received from the subscribers of Allahabad about excessive billing.

MR. CHAIRMAN : I think he will be able to give the details to you later.

SHRI RAJESH PILOT : सभापति जी, अगर पार्ट "क" को माननीय सदस्य पढ़ें तो उसमें लिखा है: The question is : 'Whether it is a fact that there are common complaints of over-billing..... against MTNL." Sir, MTNL is functioning in Delhi and Bombay only. Allahabad does not come under MTNL.

SHRI GOPALSINH G. SOLANKI : Sir, we have heard complaints with regard to telephones. In many exchanges, the telephones go out of order. I know of cases where on a particular day, the telephone has gone out of order for 7 to 8 times. Sometimes, the telephone remains dead, and when we complain against it, the officials of the department say that it is because of the old machinery and old equipment. I want to know from the hon. Minister whether there are any plans to convert these old exchanges and old equipments into computerised or other hi-tech exchanges to avoid these complaints.

SHRI RAJESH PILOT : Upgrading the technology in both the sectors—technical and computerisation—is an on-going process; it is a continuing process for the whole country. We have in the country around 45-50 computerised exchanges already and as I said, it is an on-going project in each sector of our communication system and if any hon. Member says that it is going slow in a particular area, I can have it checked up.

SHRI GOPALSINH G. SOLANKI : I am talking of Gujarat and other talukas.

SHRI RAJESH PILOT : Luckily, Gujarat is doing very well in the matter of computerisation of the system and it is slightly better than many parts of the country.

SHRI JOHN F. FERNANDES : The solution of the problem of excess billing is possible only in electronic exchanges which are available in the main metropolitan cities. In most of the States, we do not have electronic exchanges and we have only manual exchanges and it is possible for the telephone staff to manipulate. I want to know from the hon. Minister whether in places where STD facility is available, the manual exchange would be converted into electronic exchange.

SHRI RAJESH PILOT : As I said, it is an on-going process and we are trying our best. We are very keen that the whole country should be brought under electronic exchanges, and due to the Government policy of liberalisation, our department has been benefited to a great extent. Our production is increasing and this year we are likely to enhance it. I take the sense of the House that our service must improve. Every hon. Member has pointed out that we must improve our service. We will do our best to see that all these loopholes could be plugged and we are able to improve our service.

MR. CHAIRMAN : Next question.

Telecast of serials on Family Planning by Doordarshan

*103. SHRI INDER KUMAR GUJRAL : Will the Minister of INFORMATION & BROADCASTING be pleased to state : (a) Whether it is a fact that Doordarshan has undertaken telecast of some serials on family planning; and